जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 30 संख्याः 266 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 27 जुलाई, 2023 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

# मोदी सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को स्वीकृति मिली

## विपक्ष इस स्वीकृति से काफी उत्साहित

- विपक्ष का मानना है कि, अब प्र.मंत्री मोदी को लोकसभा में मणिपुर की स्थिति पर बोलने के लिये ''मजबूर'' किया जा सकेगा।
- हालांकि, सरकार का मानना है कि, देश की आंतरिक स्थिति पर गृह मंत्री भी सदन को संबोधित करते हैं, यह संसदीय परम्परा है।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव को बहस के लिये स्वीकार किया। लगभग 50 सांसदों ने खड़े होकर गोगोई के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- विपक्ष का मकसद विश्वास प्रस्ताव के मार्फत विपक्ष की एकता प्रदर्शन करना, व संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये मणिपुर की विषम स्थिति पर बहस करना भी है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। लोकसभा के अंदर मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव का स्वीकरण विपक्षी गठबंधन ''इंडिया'' के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है कि गठबंधन मणिपुर की गंभीर स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसद में बोलने के लिये बाध्य कर सकता है, जहां नृजातीय हिंसा एवं संघर्ष 3 मई से लगातार चल रहा है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मंत्रिपरिषद में स्वीकार कर लिया। इससे पूर्व, विपक्ष के 50 सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर प्रस्ताव के प्रति अपना समर्थन दर्शा दिया था।

इस संसदीय लड़ाई में, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के साधन का रणनैतिक उपयोग करने का निर्णय लिया था। इस मुहिम के अंतर्गत, गोगोई ने नियमानुसार बुधवार को प्रातः 10 बजे से पहले मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया था।

नवगठित विपक्षी गठबंधन ''इंडिया'' के हिस्से के रूप में कांग्रेस पार्टी ने तथा इसके अलावा तेलंगाना की ''भारत राष्ट्र समिति'' (बी.आर.एस.) ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में दो अलग-अलग अविश्वास प्रस्ताव पेश किये।

यह कदम तब उठाया गया, जब सत्तारूढ़ दल ''इंडिया'' की इस मांग को स्वीकार करने के लिये राजी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर बयान दें। हालांकि मोदी इस मुद्दे पर संसद के बाहर तो बोले थे लेकिन वे संसद के दोनों सदनों के अंदर कोई बयान देने के लिये तैयार नहीं थे।

इस तथ्य की पूरी जानकारी के बावजूद कि सत्तारूढ़ दल के अच्छे खासे बहुमत के चलते प्रस्ताव पराजित होगा, विपक्ष ने मणिपुर के जनजातीय संघर्ष को लेकर चल रहे संसदीय गतिरोध के बीच यह कदम उठाया है। ज्ञातव्य है कि मणिपुर के संघर्ष 125 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हो गये हैं तथा रोजाना अकथनीय वीभत्सता की नई-नई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं।

यह संघर्ष और तीन महीने से चल रही इस हिंसा के बाद भी इसे रोक पाने में सरकार की असमर्थता 20 जुलाई से शुरू हुये मानसून सत्र में शुरू से ही संसद के दोनों सदनों में कोई काम नहीं हो पाने के मुख्य कारण रहे हैं।

विपक्षी दलों द्वारा लाये गये इस अविश्वास प्रस्ताव के संख्यात्मक परीक्षा में असफल होने की पूरी-पूरी संभावना के बावजूद, विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर बहस के दौरान सरकार को घेरने से उन्हें ''छवि की लड़ाई'' में विजय मिलेगी। विपक्ष का कहना है कि इस रणनीति के फलस्वरूप, प्रधानमंत्री इस अति ज्वलंत विषय पर संसद को संबोधित करने के लिये बाध्य होंगे, भले ही सरकार इस बात पर अड़ी हुई हो कि मणिपुर की स्थिति पर होने वाली बहस का जवाब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह देंगे।

चूँकि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के लिये 272 सदस्य संख्या जरूरी है, इसलिये प्रधानमंत्री मोदी का नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) अपने 331 सदस्यों के चलते पूरी तरह सुरक्षित हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 144 सांसद हैं, जबकि के.सी.आर. की भारत राष्ट्र समिति और जगन रेड्डी की वाय.एस.आर.सी.पी. तथा बीजू जनता दल की कुल सदस्य संख्या 70 है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

## जोधपुर विश्वविद्यालय गैंगरेप केस में जांच पूरी

जोधपुर, 26 जुलाई (कासं)। शहर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में गत 16 जुलाई रविवार की अलसुबह एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है, जिसका बुधवार सुबह पॉक्सो अदालत में चालान पेश किया गया।

पुलिस उपायुक्त, पूर्व, डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में जांच अधिकारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस

- 16 जुलाई को नाबालिग के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने मात्र 10 दिन में जांच पूरी कर ली और अपराधियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया।

(ए.डी.सी.पी.) निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में गठित स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र तैयार कर लिया है। शहर में संभवतः दुष्कर्म से जुड़े किसी मामले में महज 10 दिन में जांच पूरी कर चालान पेश करने का यह पहला प्रकरण है। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ खुद भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि, 15-16 जुलाई की रात को तीन छात्र समंदर सिंह, धर्मपाल

(शेष पृष्ठ 5 पर)

# चीन के विदेश मंत्री अचानक क्यों हटाये गये?

## पदच्युत विदेश मंत्री राष्ट्रपति शी की व्यक्तिगत ''चॉइस'' थे, अतः उन्हें क्यों अचानक हटाया गया?

- इतने वरिष्ठ मंत्री को हटाना क्या चीन के राजनीतिक व प्रशासनिक सिस्टम की अपरिपक्वता व त्रुटिपूर्ण होने का लक्षण है?
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, एक तरफ तो चीन विश्व में यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि, उसकी राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था विश्व में सबसे बेहतर है तथा विश्व के अन्य देशों को उसका अनुसरण करना चाहिये। दूसरी ओर विदेश मंत्री जैसे वरिष्ठ अधिकारी व राजनीतिक हस्ती का चयन ''गलत'' साबित होना, चीन के लिये अटपटी स्थिति उत्पन्न करता है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। चीन के नवनियुक्त विदेश मंत्री चिन गांग का एकाएक गायब हो जाना देश के सर्वोच्च नेता के लिये लज्जा का विषय बन गया है।

इसका एक बड़ा कारण यह है कि अन्य बहुत से नेताओं को दरकिनार कर, चिन गांग विदेश मंत्री बनाये गये थे। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री वांग यी की जगह नियुक्त किया गया था, जो एक दशक से विदेश मंत्रालय के मुख्या रहे थे तथा एक सिद्धहस्त नेता थे।

इससे यह सिद्ध हो गया था कि चिन गांग, चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग की निजी पसंद थे। अब चिन गांग को एकाएक हटा देने का मतलब होगा- उनके निर्णय तथा अति उच्च स्तर के पद पर चयन के मामले में बहुत बड़ी गलती होना। इसका सारा दोष शी जिनपिंग के सिर जायेगा।

लेकिन किसकी मजाल है, जो शी के निर्णय की गलती के बारे में बात करे, क्योंकि यह कदम शी जिनपिंग के प्रति अंधी निष्ठा की बुनियाद पर खड़े संपूर्ण तंत्र को हिलाकर रख देगा। इसलिये, चीनी सैन्सर चीन के सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्म्स से चिन गांग के सभी संदर्भों को छाँट-छाँट कर हटा रहा है। इस पूरे परिदृश्य का एक निष्कर्ष तो यह है कि चिन का शी की कृपा से वंचित होने का कारण बहुत गंभीर- राजनैतिक मतभेद हो सकता है। अन्यथा, यह सब एकाएक और इतनी तेजी से नहीं हुआ होता। चिन तथा अमेरिका में चीनी राजदूत के रूप में उनकी गतिविधियाँ तथा हाल ही में, यू.एस. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एन्टनी ब्लिंकन के साथ उनकी मीटिंग सब कुछ पर्दे के पीछे है।

चिन चीनी राष्ट्रपति के अत्यधिक नज़दीक लोगों में से थे तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे। जब तक कोई व्यक्ति, जो पूरे तंत्र में अति महत्वपूर्ण न हो तथा शी जिनपिंग के सचमुच नज़दीक न हो, उसकी नियुक्ति एकाएक विदेश मंत्री के पद पर नहीं हो सकती थी।

चिन ने ''वुल्फ डिप्लोमेट'' की भूमिका निभाई थी, जिसे अमेरिका तथा करीब-करीब सभी पश्चिमी देशों के प्रति अपने विरोध के रूप में कुछ समय तक चीन ने प्रोत्साहित किया था। अपनी नियुक्ति के शीघ्र बाद ही, चिन मॉस्को यात्रा पर गये थे तथा वहाँ रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई थी।

लेकिन इसके कुछ समय बाद ही, वे रातों-रात सार्वजनिक परिदृश्य से गायब हो गये। इस तरह उनके एकाएक

(शेष पृष्ठ 5 पर)

# डी.एम.के. के भ्रष्टाचार व स्कैम्स की फाइल राज्यपाल को पेश

- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई ने ''डी.एम.के. फाइल्स पार्ट टू'' पेश करते हुए, एक विडियो भी जारी किया, जिसमें उनके अनुसार भ्रष्टाचार के सभी सबूत व दस्तावेज हैं
- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के अनुसार 5,600 करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार किया है, डी.एम.के. सरकार ने।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। राज्यव्यापी पदयात्रा पर निकलने से पहले भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने वादे के अनुसार ''डी.एम.के. फाइल्स पार्ट-2'' (द्रमुक) जारी की, जो डी.एम.के. के मंत्रियों के घोटालों का संकलन है जो 5600 करोड़ रूपए का है।

भाजपा नेता ने अपनी संकलित जानकारी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को एक ज्ञापन के रूप में सौंपी और कहा कि वे सत्तारूढ़ द्रमुक के मंत्रियों, विधायकों एवं सांसदों के बेनामी संपर्कों पर कार्रवाई के आदेश जारी करें।

अन्नामलाई ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वे राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं और कहा कि भाजपा डी.एम.के. फाइल्स-2 पर कार्रवाई चाहती है जिसमें डी.एममे.के. के प्रथम परिवार और उसके निकटवर्ती लोगों के कारनामों की जानकारी है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा संचालित मैडिकल कॉर्पोरेशन में 600 करोड़ रूपए, राज्य परिवहन विभाग में, 2000 करोड़ रूपए और डी.एम.के. से जुड़ी एक फर्म के मामले में 3000 करोड़ रूपए का घोटाला है और तीनों मिलाकर 5600 करोड़ रूपए हैं। भाजपा नेता ने 16 मिनट का एक वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें घोटालों के आरोप वाले दस्तावेज हैं। भगवा पार्टी ने इन्हें डी.एम.के. पार्ट-1 के बाद डी.एम.के. फाइल्स पार्ट-2 कहा है। अन्नामलाई ने कहा, ''हम अपनी पदयात्रा के दौरान प्रेम और मीडिया में अपने मित्रों को विस्तार से बताएंगे। हम भ्रष्ट डी.एम.के. सरकार से जवाब मांगते हैं।

अन्नामलाई ने डी.एम.के. के फाइल्स का पहला भाग जारी किया था जिसमें आरोप था कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को 2011 के चुनावी चंदे के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
ऑटोमेटिक कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

## बोनमैरो ट्रांसप्लांट के 60 लाख रू. मय ब्याज अदा किए जाएं

जयपुर, 26 जुलाई। जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने ई.एस.आई.सी. बीमाधारक को राहत देते हुए ई.एस.आई.सी. व राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वह परिवादी के बेटे के बोनमैरो ट्रांसप्लांटेशन सहित अन्य इलाज पर खर्च हुए 60 लाख रुपए 2 दिसंबर 2021 से सात प्रतिशत ब्याज

- जयपुर मैट्रो की स्थाई लोक अदालत ने ई.एस.आई.सी. और राज्य सरकार को परिवादी के बेटे के इलाज पर खर्च राशि लौटाने के आदेश देने के साथ ही इन पर 1.21 लाख रू. का हर्जाना भी लगाया है।

सहित दे। वहीं अदालत ने इलाज में लापरवाही बरतने और परिवादी पक्ष को हुई परेशानी पर ई.एस.आई.सी. व राज्य सरकार पर 1.21 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह ने यह आदेश दीपक पारीक के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

# 'आपका पक्ष, संसद में आपके ''एक्शन'' से मेल नहीं खाता'

## कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनको लिखे गये पत्र पर काफी सख्त टिप्पणी की

- अमित शाह ने खड़गे को पत्र लिखकर ''बहुमूल्य सहयोग'' मांगा था।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ''अमूल्य सहयोग'' के लिए प्राप्त हुए पत्र के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाबी हमला बोलते हुए लिखा कि उनके शब्द संसद में सत्तारूढ़ पार्टी की गतिविधियों से मेल नहीं खाते।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कल खड़गे को एक पत्र लिखकर विपक्ष से ''अमूल्य सहयोग'' मांगा था और उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठने को कहा था।

शाह के पत्र का जवाब देते हुए खड़गे ने संसद के वर्तमान सत्र में मणिपुर पर चर्चा की, विपक्ष की मांग दोहराई और कहा कि उनके शब्द उनके कारनामों से मेल नहीं खाते।

खड़गे ने अपने पत्र में कहा ''जो पत्र हमें आपसे मिला है वह तथ्यात्मक नहीं है। आपके शब्दों और कामो में बहुत ज्यादा अंतर है। सरकार असहनशील है और संसद पर अपनी मर्जी थोप रही है।''

उन्होंने कहा कि वे चाहते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर पर बयान दें, जिसके बाद संसद में चर्चा हो।

विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जब 4 मई की घटना का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर आया, जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया है।

मणिपुर पुलिस ने वीडियो में नज़र आ रहे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि थोउबल जिले के नोंगपोक सेकमई थाने में अपहरण गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है।

मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा भड़काने के बाद से अब तक 150 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके है।

इस बीच खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि कार्रवाई के दौरान जब वे बोल रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया गया था इस तरह से उनके ''आत्मसम्मान को चुनौती'' दी गई है।

यह प्रस्ताव सदन में आपाधापी के बीच आया, जब विपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मणिपुर में तीन महीन से चल रहे जातीय दंगों पर वक्तव्य की मांग कर रहे थे इसके जवाब में भाजपानीत गठबंधन ने ''मोदी मोदी'' के नारे लगाकर सदन में अफरातफरी मचा दी। कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''यह मेरे विशेषाधिकार का हनन है। यह मेरा अपमान है। मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी गई है। अगर सदन सरकार के निर्देशों पर चलता है तो मैं समझता हूं यह लोकतंत्र नहीं है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने भाषण के बीच व्यवधान पर नाराज़गी जताई जिससे विपक्षी सदस्यों में शोरगुल आरंभ हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपने स्थान ग्रहण करने को कहा।

जब खड़गे को सूचित किया गया कि उनके पीछे कतार में कई सांसद खड़े हैं तो कांग्रेस नेता ने कहा ''मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो क्या मोदी के पीछे खड़े होंगे। धनखड़ और कई सदस्य खड़गे की टिप्पणी पर मुस्कुरा दिए।

धनखड़ ने खड़गे तथा सदन के नेता पीयूष गोयल से स्थिति संभालने में मदद मांगी। इन प्रयासों के बावजूद गर्मागर्मी जारी रही।

सभापति ने स्पष्ट किया कि माइक

(शेष पृष्ठ 5 पर)

## कन्हैया हत्याकांड के एक आरोपी ने जमानत मांगी

जयपुर, 26 जुलाई। बुधवार को, नैशनल इन्वैस्टिगेशन एजेन्सी (एन.आई.ए.) मामलों की विशेष अदालत में उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड प्रकरण की सुनवाई एक अगस्त तक टल गई है। पीठासीन अधिकारी के

- एन.आई.ए. मामलों की विशेष अदालत में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी ने जमानत अर्जी दायर की है। कोर्ट में जमानत अर्ज़ी और हत्याकांड के मामले में एक अगस्त को सुनवाई होगी।

अवकाश पर होने के चलते मामले में बहस नहीं हो सकी। वहीं, मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। इस जमानत अर्जी पर भी एक अगस्त को सुनवाई होगी।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

# प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सीकर में कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे व किसान सम्मान निधि की राशि करेंगे जारी

## प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस साल राजस्थान में खासे सक्रिय दिख रहे हैं। बीते 9 महीनों में प्रधानमंत्री का यह आठवां दौरा होगा

- प्रधानमंत्री मोदी लाल डायरी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था सहित कई प्रकरणों का जिक्र कर सकते हैं।
- मोदी की सीकर यात्रा के राजनैतिक मायने देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2018 के चुनावों में शेखावाटी की 21 सीटों में से भाजपा को दो ही सीटें मिली थीं, इसलिए भाजपा मोदी की लोकप्रियता के आधार पर शेखावाटी में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है।
- सीकर में ही मोदी एक लाख पी.एम. किसान समृद्धि केन्द्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और किसानों को 17 हजार करोड़ रू. की 14वीं किश्त भी जारी करेंगे।
- मोदी प्रदेश में 5 नए मैडिकल कॉलेज और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे।

जयपुर, 26 जुलाई । भाजपा के मिशन मरुधरा के तहत प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को फिर से प्रदेश के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल राजस्थान में खासा सक्रिय दिख रहे हैं। बीते 9 महीनों में प्रधानमंत्री का यह आठवां दौरा होगा।

वर्ष 2022 में 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी आबू रोड आए थे, लेकिन सभा को संबोधित नहीं कर पाए थे। इसके बाद 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे। वर्ष 2023 में मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद में और 12 फरवरी को दौसा के दौरे पर रहे थे। इसके बाद 12 मई को प्रधानमंत्री नाथद्वारा और आबूरोड आए थे। प्रधानमंत्रई ने अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को अजमेर और पुष्कर का दौरा किया था और कई योजनाएं लॉंच की थीं। इसके बाद हाल ही में 8 जुलाई को मोदी ने बीकानेर का दौरा किया था।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मोदी के सीकर दौरे के राजनीतिक मायने भी देखे जा रहे हैं। सन् 2018 के चुनाव में शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू की 21 सीटों में से भाजपा 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, एक सीट बसपा और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी और भाजपा को शेखावटी की जमीन पर कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। लिहाजा माना जा रहा है कि, भाजपा का प्रयास है कि, इन 3 जिलों में पार्टी अपने आधार को मजबूत बनाए। कहा जा रहा है कि, शेखावटी में प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश में महिला सुरक्षा और लाल किताब जैसे मसलों को उठाएंगे तथा शेखावटी अंचल के विधायक राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी से लेकर निलंबन तक के मसले को भुनाएंगे तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले में पेपर लीक और युवाओं के मसले पर मौजूदा अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथ लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एक लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तकरीबन 17 हजार करोड़ रुपए की 14वीं किश्त भी जारी करेंगे।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11:15 बजे सीकर पहुंचेंगे। यहां राष्ट्रीय परियोजनाओं के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

## नैक्सा एवर ग्रीन ठगी केस की जांच सी.बी.आई. को?

जयपुर, 26 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सी.बी.आई. को नोटिस जारी कर पूछा है कि हजारों लोगों से कई हजार करोड रुपए के नैक्सा एवरग्रीन ठगी प्रकरण की जांच क्यों ना सी.बी.आई. से कराई

- राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और सी.बी.आई. को नोटिस जारी कर यह सवाल पूछा है। नैक्सा एवर ग्रीन ठगी केस के आरोपियों पर देश भर के हजारों लोगों से 11,000 करोड़ रू. ठगने का आरोप है।

जाए। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने सत्यवीर सिंह व अन्य की याचिका पर यह नोटिस जारी किए।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि प्रकरण में जयपुर और सीकर सहित

(शेष पृष्ठ 5 पर)